जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग

न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और डीए रीसेट पर टिकी कर्मचारियों की नजर

नई दिल्ली, 28 दिसंबर. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा होने जा रहा है और ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद तेज हो गई है.

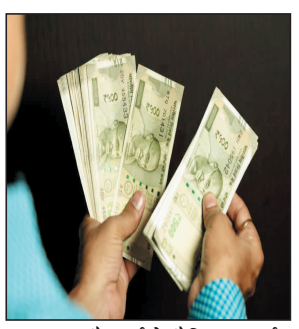

बढ़ती महंगाई और पिछले एक दशक से न्यूनतम वेतन में कोई बदलाव न होने के कारण कर्मचारी संगठनों की निगाहें नए वेतन आयोग पर टिकी हैं. 7वें वेतन आयोग ने 2016 में सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया था, ग्रेड पे खत्म किया गया था और नई पे मैट्रिक्स लाई गई थी. उस समय न्यूनतम बेसिक पे सीधे 18,000 रुपये तय किया गया था. हालांकि, अब लगभग 10 साल बाद महंगाई भत्ता (डीए) 58प्रतिशत तक पहुंच चुका है, लेकिन बेसिक वेतन जस का तस है. यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग से उच्च फिटमेंट फैक्टर और ज्यादा न्यूनतम वेतन की मांग तेज हो गई है.

6वें वेतन आयोग के अंतिम दौर में डीए 119प्रतिशत तक पहुंच गया था, जिसे देखते हुए 7वें वेतन आयोग में शून्य से शुरू किया गया था. अब एक बार फिर वही स्थिति बनती दिख रही है. लेवल-1 कर्मचारी की मौजूदा सैलरी डीए और एचआरए जोड़ने के बाद 33,000-34,000 रुपये तक पहुंच चुकी है, लेकिन महंगाई के मुकाबले यह अपर्याप्त मानी जा रही है.

> विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है. न्यूनतम बेसिक पे में बड़ा इजाफा हो सकता है. डीए को दोबारा रीसेट किया जा सकता है.पेंशनर्स को भी सीधा लाभ मिल सकता है. कर्मचारियों को कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद. यदि फिटमेंट फैक्टर 3.0 या उससे अधिक तय होता है, तो न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये या उससे ऊपर जा सकता है. इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में बड़ा उछाल आएगा. कर्मचारी संगठन इसे महंगाई और जीवन-यापन की लागत के हिसाब से जरूरी सुधार बता रहे हैं.

एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार से निकाले 74,822 करोड़ रुपए

मुंबई, 28 दिसंबर. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस साल 26 दिसंबर तक भारतीय पूंजी बाजार से 74, 822 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी है. शुद्ध निकासी का मतलब है कि उन्होंने जितना पैसा बाजार में लगाया है उससे 74,822 करोड़ रुपये ज्यादा निकाले हैं.

अकेले दिसंबर में अबतक 29,571 करोड़ रुपये की निकासी की गयी है जो जनवरी के बाद सबसे अधिक है. साल के 12 में से आठ महीने एफपीआई बिकवाल रहे हैं जबकि शेष चार महीने वे शुद्ध रूप से लिवाल रहे हैं. सीडीएसएल के आंकड़ों के अनुसार, पूरे साल के दौरान एफपीआई ने शुद्ध रूप से 1,52,227 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची. वहीं, उन्होंने जमकर डेट में खरीदारी की.

उन्होंने 72,893 रुपये के डेट की शुद्ध खरीदी की. म्यूचुअल फंड में उनका शुद्ध निवेश 10,877 करोड़ रुपये रहा. हाइब्रिड उपकरणों में भी उन्होंने 1,442 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया. दिसंबर में एफपीआई ने 14,734 करोड़ रुपये की इक्विटी की शुद्ध बिकवाली की. महीने के दौरान डेट, हाइब्रिड उपकरणों और म्यूचुअल फंड में भी उनका निवेश नकारात्मक रहा.

आर्थिक आंकड़ों से तय होगी बाजार की चाल

मुंबई, 28 दिसंबर. घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर रहेगी. अगले सप्ताह सोमवार को औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी किये जायेंगे.

इसके बाद 02 जनवरी को औद्योगिक क्षेत्र के खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के आंकड़े जारी होंगे और सप्ताह के दौरान ही वाहनों की बिक्री के आंकड़े भी आयेंगे. बीते सप्ताह गुरुवार को क्रिसमस के अवकाश के कारण बाजार में चार दिन ही कारोबार हुआ. बीएसई के 30 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 112.09 अंक (0.13 प्रतिशत) की साप्ताहिक बढ़त रही और यह शुक्रवार को 85,041.45 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी सप्ताह के दौरान 75.90 अंक यानी 0.29 प्रतिशत चढ़कर 26,042.30 अंक पर पहुंच गया. मझौली कंपनियों का निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.48 प्रतिशत गिर गया. स्मॉलकैप-100 सूचकांक में 1.75 प्रतिशत की तेजी रही. सप्ताह के दौरान सेंसेक्स की 30 में से 17 कंपनियों के शेयर बढ़त में और अन्य 13 के गिरावट में रहे. ट्रेंट का शेयर सबसे अधिक 5.47 प्रतिशत मजबूत हुआ. अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.59 फीसदी, टाइटन में 1.56, बीईएल में 1.44, एनटीपीसी में 1.30, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 1.14 प्रतिशत और मारुति सुजुकी में एक प्रतिशत की तेजी रही.

सोना-चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड! कीमतें आसमान पर

1.41 लाख रुपए पर पहुंचा सोना

2.35 लाख रुपए हो गई चांदी

नई दिल्ली 28 दिसंबर. आज सोने और चांदी की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं. 24 कैरेट सोना लगभग 1,41,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,35,000 प्रति किलो के पार पहुँच गई है.

पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़त के कारण निवेशक उत्सुक हैं और बाजार में हल्की घबराहट भी देखी जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस उछाल का मुख्य कारण वैश्विक बाजार के रुझान और डॉलर की मजबूती है. अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़े संकेत भी सोने और चांदी के भाव को प्रभावित कर रहे हैं. मुख्य बातें-ऐतिहासिक ऊंचाई- सोना और चांदी अब तक के उच्चतम स्तर पर.बड़ी उछाल- चांदी में इस साल 150प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी, सोने में भी भारी उछाल. शहरों में असर- लखनऊ, कानपुर, पटना और भोपाल में भी कीमतें आसमान छू रही हैं.

मुद्रा लोन से 52 करोड़ लोगों को मिला लाभ

राउंडअप 2025

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए भारत सरकार की ओर से एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत बिना किसी गारंटी के जरूरत मंद लोगों को लोन की सुविधा दी जाती है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म उद्यमियों को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराना और छोटे कारोबार को शुरू व विस्तार में मदद देना है. इसके लिए बैंक शाखाओं, एनबीएफसी और एमएफआई के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, जिसमें आधार-पैन और संक्षिप्त बिज़नेस प्लान जरूरी होता है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत रुपए 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है. यह लोन शिशु, किशोर और तरुण—तीन श्रेणियों में उपलब्ध है. योजना का उद्देश्य व्यापार, सेवा, विनिर्माण और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देना है. मुद्रा लोन के लिए जनसमर्थ पोर्टल या बैंकों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. अब तक इस योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता को मजबूती मिली है और लाखों लोग स्वरोजगार की ओर बढ़े हैं.

2025 में योजना का फोकस लोन सीमा बढ़ाने, नई श्रेणियां जोड़ने और महिला व वंचित वर्गों को सशक्त करने पर है. एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार, एमएसएमई ऋण वित्त वर्ष 2014 के 8.51 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में 27.25 लाख करोड़ हो गया है, जो रोजगार और आत्मनिर्भरता को मजबूती दे रहा है. पीएमएमवाई के तहत स्वीकृत और वितरित ऋणों का विश्लेषण बताता है कि यह योजना आर्थिक पिरामिड के निचले स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंची है. औसत ऋण राशि में लगातार वृद्धि—वित्त वर्ष 2025 में 1.02 लाख—बढ़ते कारोबारी विश्वास और बाजार विस्तार का संकेत है.

पीएम मुद्रा योजना : लोन सीमा 20 लाख

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वर्ष 2025 में बड़ा बदलाव किया गया है. केंद्र सरकार ने तरुण श्रेणी की लोन सीमा रुपए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है, जिसे नाम दिया गया है. इस फैसले से छोटे और लघु व्यवसायों को विस्तार के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होगी. किन बैंकों से मिलेगा मुद्रा लोन- 2025 में मुद्रा लोन देश के सभी प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ज़रिए उपलब्ध है—सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक-स्टेट बैंक ऑफ बड़ोदा,बैंक ऑफ बड़ोदा, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक,यूनियन बैंक ऑफ बड़ोदा, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक सहित अन्य सरकारी बैंक अन्य संस्थान-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस संस्थान, मुद्रा लोन की कैटेगरी (2025), शिशु 50,000 तक ङ्क नया व्यवसाय शुरू करने के लिए किशोर- 50,001 से 5 लाख मौजूदा कारोबार के विस्तार के लिए 2025 के मुख्य अपडेट्स- लोन सीमा में इजाफा- 2024-25 के बजट के बाद तरुण कैटेगरी को बढ़ाकर 'तरुण+' किया गया.

सीमा शुल्क विभाग ने सहयोग और विश्वास पर दिया जोर

नई दिल्ली, 28 दिसंबर. सीमा शुल्क विभाग के दिल्ली जोन ने कहा है कि निर्यात-आयात कारोबार में लगे समुदाय के साथ विश्वास, प्रणाली की दक्षता और साझा उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वह सरकारी एजेंसियों और हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग चाहता है.

वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली सीमा शुल्क विभाग द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर दिल्ली जोन के मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त की अध्यक्षता में सीमा शुल्क मंजूरी सुविधा समिति (सीसीएफसी) की बैठक में विभाग के अधिकारियों ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और कानून के दायरे में व्यापार सुविधा को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

बैठक कहा गया कि क्षेत्र का मार्गदर्शक सिद्धांत पारदर्शिता, सुलभता और दक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है. ये मूल्य न केवल सीमा शुल्क के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि विश्वास निर्माण और यह सुनिश्चित करने का आधार हैं. विश्वास के आधार पर ही हितधारक प्रशासन के साथ खुलकर संवाद करने में सक्षम महसूस कर सकते हैं.

व्यापारिक समुदाय के बीच निरंतर सहयोग आवश्यक

भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र ने इस बात पर ज़ोर दिया कि व्यापार में सुगमता एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके लिए सीमा शुल्क विभाग, सहयोगी एजेंसियों, संरक्षकों और व्यापारिक समुदाय के बीच निरंतर सहयोग आवश्यक है. मुताबिक निर्णय में पारदर्शिता, प्रक्रियाओं में सुगमता और संवाद एवं समस्या-समाधान के लिए खुली नीति को अपनाकर, दिल्ली सीमा शुल्क विभाग विश्वास, दक्षता और साझा उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता है. यह बैठक आयात और आयात कारोबार में सुगमता और भरोसा बनाये रखने और बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास है. इस बैठक में एफएसएसएआई, प्लांट क्वारंटाइन और ड्रग कंट्रोलर सहित सहयोगी सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ कस्टम्स ब्रोकर, एसोचैम और जीजेईपीसी जैसे व्यापार संघों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.

धीरूभाई की जयंती पर छात्रवृत्ति योजना की घोषणा

देश के 5100 होनहार छात्रों को रिलायंस फाउंडेशन का सहारा

मुंबई , 28 दिसंबर. रिलायंस फाउंडेशन ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की छात्रवृत्ति के लिए इस साल देश भर से क्रमश- 5,000 और 100 योग्य अभ्यर्थियों को चुना है. इसके तहत स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को क्रमश: दो लाख रुपये और छह लाख रुपये की सहायता दी जाती है.

रिलायंस उद्योग समूह के सामाजिक कार्यों में लगे इस प्रतिष्ठान ने समूह के संस्थापक स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी की 93वीं जयंती पर इस साल की छात्रवृत्ति के निर्णयों की शनिवार को घोषणा की. प्रतिष्ठान अब तक 33437 युवाओं को छात्रवृत्ति दे चुका है. रिलायंस फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि यह छात्रवृत्ति योजना रिलायंस फाउंडेशन की युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता में एक और कदम है, जो रिलायंस के संस्थापक चेयरमैन स्वर्गीय श्री धीरूभाई अंबानी के सपनों से प्रेरित है. 2022 में, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने 10 सालों में 50,000 स्कॉलरशिप देने की अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने की घोषणा की थी.

सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 35,439 करोड़ रुपए घटा

मुंबई 28 दिसंबर. सेंसेक्स में तेजी के बावजूद पिछले सप्ताह बीएसई की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 35,439 करोड़ रुपये घट गया जबकि अन्य तीन का 22,113 करोड़ रुपये बढ़ा. बाजार पूंजीकरण के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे अधिक 12,692 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया. विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का एमकैप 8,255 करोड़ रुपये और बजाज फाइनेंस का 5,102 करोड़ रुपये घट गया.

चावल और खाद्य तेलों में साप्ताहिक तेजी, दालों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 28 दिसंबर. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव बढ़ गये. वहीं, गेहूं और चीनी के भाव लगभग स्थिर रहे. खाद्य तेलों में तेजी रही जबकि दालों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा.

घरेलू थोक जिंस बाजारों में सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत दो रुपये की मामूली बढ़त के साथ सप्ताहांत पर 3,829 रुपये प्रति क्विंटल रही. गेहूं 2,857 रुपये प्रति क्विंटल पर कमोबेश अपरिवर्तित रहा. आटा छह रुपये महंगा हुआ और 3,311 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया. बीते सप्ताह खाद्य तेलों में तेजी देखी गयी. वनस्पति की कीमत 142 रुपये और सरसों तेल की 121 रुपये बढ़ गयी. सूरजमुखी तेल में 74 रुपये और मूंगफली तेल में 47 रुपये प्रति क्विंटल की साप्ताहिक बढ़त रही. सोया तेल 41 रुपये और पाम ऑयल 38 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ. सप्ताह के दौरान चना दाल 12 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई. तुअर दाल की कीमत 66 रुपये और उड़द दाल की 38 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी.

समाचार विशेष

डिप्टी स्पीकर ने छोड़ी कुर्सी

मोदी के गृह राज्य में मचा सियासी हड़कंप

अहमदाबाद. पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात की सियासी गलियारों से एक बड़ी ख़बर सामने आई है. जहां विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई अहीर भारवाड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. जिसके बाद सूबे में सियासी हलचल बढ़ गई है.

जानकारी के मुताबिक, भरवाड़ ने नाफेड समेत विभिन्न सहकारी संस्थाओं के कार्यों में समय देने और अपने अन्य दायित्वों को निभाने के कारण यह निर्णय लिया है. आपको बता दें कि मध्य गुजरात में जेठाभाई अहीर भारवाड़ एक प्रमुख सहकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं और सहकारी क्षेत्र में उनका विशेष दबदबा रहा है. भरवाड़ अब्दासा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. कहा जा रहा है कि उन्होंने यह इस्तीफा अपने सहकारी कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने के उद्देश्य से दिया है.

गुजरात के सीएम भूपेंद्रभाई पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगदीशभाई विश्वकर्मा और संगठन मंत्री रत्नाकरजी की उपस्थिति में जेठा भरवाड़ ने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपा. राज्य विधानसभा अध्यक्ष शंकरभाई चौधरी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. जिसके चलते विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद फिलहाल रिक्त हो गया है.

गुजरात में बढ़ गई राजनैतिक हलचल

इसके अलावा एक चर्चा यह भी है कि जेठाभाई अहीर भारवाड़ से इस्तीफा इस वजह से दिलवाया गया है, जिससे किसी और नेता को यह पद सौंपा जा सके. डिप्टी स्पीकर के अचानक इस्तीफे से राज्य में राजनैतिक हलचल जरूर बढ़ गई है. सवाल यह भी उठ रहा है कि गुजरात में क्या कुछ चल रहा है? हालांकि, इस फैसले की पीछे की असली वजह क्या है? इसका ठीक-ठीक बयान कर पाना मुश्किल है. फिलहाल सियासत में कुछ भी अधिक समय तक छुपकर नहीं रह सकता. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर इस्तीफे का क्या कुछ कारण सामने आता है.

श्रापित हस्तिनापुर से तीसरी बार नहीं लड़ूंगा चुनाव

किस बात से डर रहे योगी के मंत्री

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री और हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक का एक बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मंच से यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हस्तिनापुर की श्रापित धरती से मैं तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ूंगा. यह बयान मंत्री ने खरखौदा में आयोजित एक स्कूल कार्यक्रम के दौरान दिया.

मंच से बोलते हुए दिनेश खटीक ने हस्तिनापुर की पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र से जुड़ा एक मिथक लंबे समय से प्रचलित है, जिसे लेकर वे खुद भी चिंतित हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हस्तिनापुर की धरती ऐतिहासिक रूप से

श्रापित मानी जाती रही है, और यही कारण है कि यहां से राजनीति करने वाले नेताओं को बहुत सोच-समझकर कदम उठाने चाहिए.

दोबारा जीतकर राजनीतिक मिथक तोड़ा- खटीक ने हाल ही में हस्तिनापुर से दोबारा विधायक बनकर एक बड़ा राजनीतिक मिथक तोड़ा है. कहा जाता रहा है कि इस सीट से कोई भी व्यक्ति दोबारा विधायक नहीं बन पाता, लेकिन खटीक ने लगातार जीत दर्ज कर इस धारणा को गलत साबित किया. हालांकि, उन्होंने मंच से यह स्वीकार किया कि वे तीसरी बार चुनाव लड़ने को लेकर आशंकित हैं.

द्रौपदी के श्राप का जिक्र

अपने भाषण में मंत्री ने महाभारत कालीन संदर्भों का उल्लेख करते हुए द्रौपदी के श्राप की बात भी की. उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर की धरती का ऐतिहासिक महत्व है और यह श्रापित मानी जाती रही है, जिससे यहाँ से राजनीति करने वालों को अपने कदम सावधानी से उठाने चाहिए. दिनेश खटीक ने एक और चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि हस्तिनापुर से जिस पार्टी का विधायक बनता है, प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनती है. इस कथन ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है. इसे आगामी राजनीतिक संकेतों और सत्ता समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है.

यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट के क्या मायने?

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों की लामबंदी पर अब पार्टी में ही घमासान शुरू गया है यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भविष्य में ऐसे किसी भी आयोजन को अनुशासनहीनता मान कर कार्रवाई की चेतावनी दी है, इसके बाद से विपक्षी दलों सपा हो या कांग्रेस ने ब्राह्मण वोट के महत्व को समझते हुए खुलकर ऑफर देने शुरू कर दिए हैं.

उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण है. इसमें भी शक नहीं की ब्राह्मण वर्ग के मतदाताओं की उत्तर प्रदेश में करीब 10 से 11 फ़ीसदी की भागीदारी है ऐसे में इस बड़े वोट बैंक को अपने पाली में लाने का लालच सभी सियासी दलों को रहता है खासतौर से मायावती के सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग के बाद तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण मतदाताओं का कद इतना ऊंचा हो गया है जिसे सभी सियासी दलों को मजबूर किया कि वह ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर चलें. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुशीनगर से ब्राह्मण विधायक पीएनपाठक के घर पर ब्राह्मण विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के सहभोज की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मुसीबत का सबब बन गई है.

अब जबकि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने ही भाजपा विधायकों को यह हिदायत जारी की गई तो उसके बाद तो जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया. दोनों प्रमुख विपक्षी दलों ने अपने-अपने स्तर पर ब्राह्मण विधायकों को अपने पक्ष में आने के लिए ऑफर जारी कर दिया.

ब्राह्मण विधायक निराश क्यों?

भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कल 52 ब्राह्मण विधायकों में से 46 ब्राह्मण विधायकों ने एकजुटता दिखाते हुए बैठक में ब्राह्मण के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की थी. बैठक में शामिल विधायक शलभ मणि त्रिपाठी के अनुसार बैठक में यह माना गया था कि उत्तर प्रदेश का 90 फ़ीसदी ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी को खुलकर वोट करता है फिर भी उन्हें सरकार में वह भागीदारी नहीं मिली जिसकी अपेक्षा थी और संगठन में भी उनका वर्चस्व कम हो रहा है. इस बैठक को मानसून सत्र में हुए छत्री विधायकों की बैठक के जवाब से जोड़कर देखा गया हालांकि बैठक में शामिल होने वाले ब्राह्मण विधायक इससे इनकार कर रहे हैं.

विशेष | डीके शिवकुमार ने खरगे से की मुलाकात, फिर कुर्सी पर चर्चा?

कर्नाटक का कलह फिर पहुंचा दिल्ली!

बेंगलुरु. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर उनसे मुलाकात की. इस मुलाकात ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को तुरंत हवा दे दी. बैठक के समय को लेकर सवाल उठने लगे.

हालांकि शिवकुमार ने बातचीत के तुरंत बाद पत्रकारों से कहा कि दोनों के बीच इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई. पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई. उनके

मुताबिक, बातचीत पूरी तरह से केंद्र द्वारा मनरेगा के नाम को बदलने के कदम और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर केंद्रित थी. उपमुख्यमंत्री ने कहा, किसी अन्य मुद्दे को उठाने का कोई कारण नहीं था. ना ही मैंने ऐसा किया और न ही करूंगा. वर्तमान में ऐसा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है. मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और मैंने दोनों ने स्पष्ट किया है कि हम आलाकमान के फैसले के अनुसार काम करेंगे इसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. वहीं शिवकुमार ने खुद को पदों के दावेदार के रूप में नहीं बल्कि एक आजीवन कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पेश किया.

सीएम की कुर्सी के लिए रस्साकशी जगजाहिर

यह पूछे जाने पर कि क्या अब दिल्ली इस मामले को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करेगी, शिवकुमार ने कहा कि उनकी राजधानी जाने की कोई योजना नहीं है और अगर पार्टी उन्हें बुलाएगी तो वे जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा कोई बुलावा नहीं आया है. पिछले कुछ महीनों से कर्नाटक कांग्रेस में सीएम की कुर्सी के लिए रस्साकशी जगजाहिर है. सिद्धारमैया और शिवकुमार के समर्थक आए दिन आमने-सामने होते रहे हैं.